(d) the steps taken by Government to resolve the issues involved?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHA-NAN): (a) and (b) Sir, Groups 'B* and *C officers of the Central Excise, Customs and Income Tax were on strike from 10th November, 1998 to 12th November, 1998. But international air-ports, major and minor ports and cargo complexes were not paralysed.

(c) The employees were demanding higher pay scales and improvement in some of the service conditions. The strike did not lead to any loss, of revenue.

(d) The demands are being examined.

IDBI's tie up with us based principal financial group

2533. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:

SHRI GAYA SINGH:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Industrial Development Bank of India (IDBI) is considering a proposal to tie up with the US based Principal Financial Group for management of Provident and Pension Funds in the country; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHA-NAN): (a) and (b) Industrial Development Bank of India (IDBI) has reported that Principal Financial Group, a leading provider of pension products based in the United States has held preliminary discussions with IOSI Capital Market Services Ltd., a subsidiary of IDBI to Explore the possibility of a tie up for management of provident and pension funds in India.

न्यु इंडिया एश्योरेंस कम्पनी की स्वायत्तता

2543. **श्री जनेश्वर मिश्र**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी के आधिकारियों ने साधारण बीमा निगम (जी. आई. सी.) से स्वायत्तता की मांग की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन्होने आरोप लगाया है कि साधारण बीमा निगम (जी. आई. सी.) के नियंत्रण में कार्य करते हुए इनकी कम्पनी को घाटा हुआ है;

(ग) यदि हां, तो सरकार की उक्त मांग पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या यह भी सच है कि भारत में बीमा क्षेत्र में प्रीमियम की राशि बहुत कम है; और

(ड) यदि हां, तो सरकार भारत में बीमा प्रीमियम कि राशि बढ़ाने हेतु क्या कदम उठा रही है?

वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दन): (क) जी, हां। यह सूचित किया गया है कि अधिकारी संघ ने कलकत्ता में हाल में सम्पन्न विचारगोष्ठी में कम्पनी को स्वायत्ता प्रदान करने सम्बन्धी मांग को सामने रखा था।

(ख) और (ग) जी, नहीं। न्यू इंडिया द्वारा यह सूचित किया गया है कि यह गलत है और इस बयान का कोई आधार नहीं है।

(घ) और (ड) देश में व्याप्त संभाव्यता की तुलना में साधारण बीमा क्षेत्र में प्रीमियम की राशि कम है। देश में बीमा प्रीमियम कि राशि मे वृद्धि करने के लिए लोगों के मध्य जागरूकता बढ़ाने,बीमा प्रभाव बढ़ाने, बोर्ड द्वारा कार्यनिष्पादन की समीक्षा, उत्पादों के नई तरीकों, नयी सूचना प्रोद्योगिकियों को अपनाने आदि जैसे कई उपाय किए जा रहे है।

नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को लोकल एरिया बैंक खोलने की अनुमति

2535. **श्री जनेश्वर मिश्र**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पी. एच. डी. चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री ने यह अनुरोध किया है कि "ए" क्रेडित रेटिंग से सम्पन्न नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को लोकल एरिया बैंक खोलने के अनुमति मिलनी चाहिए;

0 (ख) क्या यह भी सच है कि इनके अनुसार बैंको को इन नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों की मदद करनी चाहिए तथा इन्हें बड़े बैंको और खुदरा ग्राहकों के बीच कडी का काम करना चाहिए ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर जनार्दनन): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्हें स्थानीय क्षेत्र बैंकों के रूप में कार्य करने के लिए "ए" ऋण पात्रता वाले गैर-बैंककारी वित्तिय कम्पनियों को अनुमति देने हेतु वाणिज्य और उद्योग पी. एस. डी. चैम्बर्स से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान मार्गनिर्देशों के अनुसार गैर-बैंककरी वित्तिय कम्पनीयों स्थानिय क्षेत्र बैंको की स्थापना के लिए प्रवर्तको के रुप में आवेदन कर सकती है

(ख) उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्र ही नही उठता।

New amnesty scheme to unearth gold

2536. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government propose to introduce a new amnesty scheme to unearth huge quantities of gold lying hidden in the country;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) by when the scheme is likely to come in vogue; and

(d) what is the expected amount of gold likely to be brought out?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHA-NAN): (a) No, Sir.

(b) to (d) In view of (a) above does not arise.

उत्तर प्रदेश के गढ़वाल और कुमायूं संभागों में राष्ट्रीय बैंको की शाखाएं

2537. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के गढ़वाल और कुमायूं संभागों के पर्वतीय क्षेत्रों में सरकरी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक गांव के 10 किलोमीटर के दायरे में 15 से 25 गांवो के लिए बैकिंग सुविधा सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंको की शाखाएं खोली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन शाखाओं का जमा और ऋण का अनुपात क्या है; और

(ग) क्या सरकार व्यासघाट, जिला पौढ़ी गढ़वाल क्षेत्र के 25-30 गांवों की मांग पर व्यासघाट में पंजाब नेशनल बैंक या भारतीय स्टेट बैंक की शाखा खोलने का विचार रखती है?

वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन): (क) भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत, देश के कम विकसित पर्वतीय क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त बैंक शाखाएं खोलने की आवश्यकता के मूल्याकंन का कार्य अलग-अलग बैंको के निर्णय पर छोड़ गया है और कोई राज्य-वार / क्षेत्र – वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए है । उन केन्द्रों में जो आवेदक बैंक के सेवा क्षेत्र में आते है और जो संबंधित राज्य सरकार द्वरा संस्तुत है,। अतिरिक्त ग्रामीण शाखाए खोलने के लिए बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों पर गुण-दोषों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विचार किया जाता है ।

(ख) मार्च 1998 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश के गढ़वाल और कुमाऊ के पर्वतीय क्षेत्र में अनुसूचित वाणिज्यक बैंको की कुल जमाराशियां सकल बैंक ऋण